

SHRI S. M. BANERJEE : I want to know whether there will be no retrenchment in these factories.

MK. DEPUTY-SPEAKER : Kindly read the statement which he has laid on the Table of the House. Whatever action is proper will be taken.

STATEMENT

Mr. Speaker, Sir, the services' requirements for Clothing items steeply increased in the wake of the emergency in 1962. To meet the sudden increase in the demand of the Services, capacity in the Ordnance Clothing Factories had to be increased considerably at short notice. The Clothing Factories had to resort to large scale recruitment of man-power besides purchase of manufacturing equipments. The deficiencies in the Clothing items required by the services were made up to a large extent by the Ordnance Factories by 1963-64 with the result that demands of the Services' for subsequent years have been less. The reduction of workload on the Clothing Factories was thus mainly on account of decline in the demands of the Services, and not due to diversion of orders to trade.

Efforts have been made in the past and are still being made to procure adequate workload for the Clothing Factories, by diversification of production by undertaking manufacture of items such as Tents, Durries, etc., required by the Services, by approaching other Central Government Departments for orders for garments/uniforms, by undertaking manufacture of civilian garments for sale inside the country and for export etc. These efforts have not been entirely successful and although as a result of concerted action on the above lines and phasing out the available workload on a rational basis, placement of workmen in the Ordnance Clothing Factories on idle time was avoided upto May 1969, it became inescapable to place a certain number of workmen on idle time thereafter on account of shortage of workload. Details of the total number of workmen placed on idle time in all the Ordnance Clothing Factories on account of shortage of workload are as follows :—

Month	Approximate number placed on idle time
June, 1969	150
July, 1969	824

August, 1969	1799
September, 1969	1799
October, 1969	1829
November, 1969	2829
December, 1969	2829
(upto date)	

There has, however, been no retrenchment on account of shortage of workload in the Clothing Factories. Workmen placed on idle time are paid idle time wages which includes full time wages, D.A. and other allowances normally admissible to the workers concerned and thus no financial hardship is caused to them. This Ministry is also fully seized of the matter and vigorous efforts are in hand at the highest level for obtaining more workload for the Clothing Factories.

16.59 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Forty-second Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : Sir, I beg to present the Forty-second Report of the Business Advisory Committee.

For the information of the House I may state that one of the decisions and recommendations of the Business Advisory Committee is to have a sitting of this House on Saturday, the 13th December, 1969.

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : Why ?

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : Why ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : It was unanimously agreed in order to complete the workload.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : We have agreed to half-an-hour's extension. We are sitting up to 6.30 ; previously we were sitting up to 6. Now you want a sitting again on Saturday.

SHRI RAGHU RAMAIAH : All the parties have agree to this.

MR. DEPUTY SPEAKER : The report will be debated on Friday. The Minister is just giving you advance notice.

Now we may take up the motion of Mr. Kanwar Lal Gupta to discuss the statement made by the Minister of Law and Social Welfare on the 19th November, 1969 regarding mid-term Parliamentary elections.

— — —

17.00 hrs.

DISCUSSION ON STATEMENT RE :
MID-TERM PARLIAMENTARY
ELECTIONS

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Kanwar Lal Gupta.

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) :
उपाध्यक्ष जी आज से कई दिन पहले मन्त्री महोदय ने जब मतदान सूची के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि ये सूचियाँ सर्वसाधारण रीति से बनाई जा रही हैं और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि यह सदन भंग नहीं किया जायेगा—इस प्रकार का विश्वास दिलाया था। इस वक्तव्य से केवल उनका समाधान तो हो सकता है लेकिन मैं कह सकता हूँ और कोई दूसरा आदमी इस देश में नहीं है जिसका समाधान उनके वक्तव्य से हुआ हो। जिस तरीके से श्री जिस जल्दबाजी से एलेक्शन कमीशन यह सूची बना रहा है, और जिस तरह के वक्तव्य एलेक्शन कमीशन ने दिया है कि वह 35 दिन में चुनाव करा सकता है और उसके बाद पांच लाख लोग इन सूचियों को बनाने में लगे है उससे स्पष्ट है कि यह सर्वसाधारण रीति से नहीं है। ढाई साल हो गए चुनाव हुए, इस प्रकार की सूचियाँ आपने पहले क्यों नहीं बनाई? आज जो कर रहे हैं, क्या पिछले साल भी आपने बंसा ही किया था या उससे पहले साल बंसा ही किया था? मैं कह सकता हूँ कि नहीं किया। मैं मानता हूँ कि विधान ने एलेक्शन कमीशन को जो काम सौंपा

है, एलेक्शन कमीशन को वह कार्य पूरा करना चाहिए लेकिन जिस समय में, जिस जल्दबाजी से और जिस तरीके से यह काम चुनाव आयोग कर रहा है, जबकि कांग्रेस टूटी, उसके दो टुकड़े हुए, ऐसे समय में यह बात करना और ऐसा अवसर ढूँढ़ना, मैं समझता हूँ यह स्पष्ट करता है कि चुनाव आयोग कांग्रेस के एक पक्ष को मदद देना चाहता है। इसलिए यह बड़ी खतरनाक परम्परा होगी। अगर यह बात सर्वसाधारण है तो फिर जो उप चुनाव थे प्रसेम्बली और पार्लमेन्ट के, जिनकी तिथियाँ भी निश्चित हो गई थी, उनको आपने पोस्टपोन क्यों किया। उसका कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं रखा कि जिनकी सूचियाँ तैयार हो गई थीं उनको भी आपने क्यों पोस्टपोन कर दिया। मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग का यह फर्ज था कि वह पोलिटिकल पार्टीज को और इस देश को विश्वास में लेती कि हम क्यों वाई एलेक्शन पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन उसके बजाये सारे देश में चुनाव आयोग ने एक अस्थिरता का वातावरण पैदा कर दिया ताकि पार्लियामेन्ट के जो मेम्बरस हैं जिनमें से कुछ नहीं चाहते कि पार्लमेन्ट टूट जाये वे प्रधान मन्त्री के साथ चिपके रहें। इस तरीके से चुनाव आयोग ने यह तनाव लटका कर के प्रधान मन्त्री का जो पक्ष है उस को मजबूत करने की कोशिश की है...(ब्यवधान)...मैं कहना चाहता हूँ कि यह बहुत खतरनाक परम्परा है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। इतना ही नहीं कि वह निष्पक्ष रहे बल्कि उस के लिए यह बहुत जरूरी है कि यह मालूम होना चाहिए सभी को कि वह निष्पक्ष है। मैं कह सकता हूँ कि चुनाव आयोग ने इस प्रकार का वातावरण बन कर के अपना जो कर्तव्य है उस में लापरवाही की है। अगर वह अपनी एफिशियेंसी बढ़ाने के लिए कुछ काम करते तो मुझे कोई एतराज नहीं था। लेकिन जिस समय में उन्होंने इस काम को चुना मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं नहीं है। इतना ही नहीं अगर चुनाव जल्दी हो और चुनाव